CLASS: 10th (Secondary) 1957/1907

Series: Sec. M/2017

Total No. of Printed Pages : 64 SET: A, B, C & D

MARKING INSTRUCTIONS AND MODEL ANSWERS SOCIAL SCIENCE

(History, Political Science, Geography and Economics)

(Academic/Open)

(Only for Fresh Candidates)

उप-परीक्षक मूल्यांकन निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। यदि परीक्षार्थी ने प्रश्न पूर्ण व सही हल किया है तो उसके पूर्ण अंक दें।

General Instructions:

- (i) Examiners are advised to go through the general as well as specific instructions before taking up evaluation of the answerbooks.
- (ii) Instructions given in the marking scheme are to be followed strictly so that there may be uniformity in evaluation.
- (iii) Mistakes in the answers are to be underlined or encircled.
- (iv) Examiners need not hesitate in awarding full marks to the examinee if the answer/s is/are absolutely correct.
- (v) Examiners are requested to ensure that every answer is seriously and honestly gone

through before it is awarded mark/s. It will ensure the authenticity as their evaluation and enhance the reputation of the Institution.

- (vi) A question having parts is to be evaluated and awarded partwise.
- (vii) If an examinee writes an acceptable answer which is not given in the marking scheme, he or she may be awarded marks only after consultation with the head-examiner.
- (viii If an examinee attempts an extra question, that answer deserving higher award should be retained and the other scored out.
- (ix) Word limit wherever prescribed, if violated upto 10%. On both sides, may be ignored. If the violation exceeds 10%, 1 mark may be deducted.
- (x) Head-examiners will approve the standard of marking of the examiners under them only after ensuring the non-violation of the instructions given in the marking scheme.
- (xi) Head-examiners and examiners are once again requested and advised to ensure the authenticity of their evaluation by going through the answers seriously, sincerely and honestly. The advice, if not headed to, will bring a bad name to them and the Institution.

महत्त्वपूर्ण निर्देश :

- (i) अंक-योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। अंक-योजना में दिए गए उत्तर-बिन्दु आंतिम नहीं हैं। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं। यदि परीक्षार्थी ने इनसे भिन्न, किन्तु उपयुक्त उत्तर दिए हैं, तो उसे उपयुक्त अंक दिए जाएँ।
- (ii) शुद्ध, सार्थक एवं सटीक उत्तरों को यथायोग्य अधिमान दिए जाएँ।
- (iii) परीक्षार्थी द्वारा अपेक्षा के अनुरूप सही उत्तर लिखने पर उसे पूर्णांक दिए जाएँ।
- (iv) वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में अधिक अंक देकर प्रोत्साहित न करें।
- (v) भाषा-क्षमता एवं अभिव्यक्ति-कौशल पर ध्यान दिया जाए।
- (vi) मुख्य-परीक्षकों / उप-परीक्षकों को उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए केवल Marking Instructions/ Guidelines दी जा रही है, यदि मूल्यांकन निर्देश में किसी प्रकार की त्रुटि हो, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो, मूल्यांकन निर्देश में दिए गए उत्तर से अलग कोई और भी उत्तर सही हो तो परीक्षक, मुख्य-परीक्षक से विचार-विमर्श करके उस प्रश्न का मूल्यांकन अपने विवेक अनुसार करें।

सामान्य निर्देश :-

- (i) मूल्यांकन निर्देश परीक्षकों हेतु केवल निर्देश हैं जो केवल मूल्यांकन कार्य में एकरूपता, समानता एवं वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, परन्तु मूल्यांकन कार्य में परीक्षक की विद्वता एवं विवेक का प्रयोग ही हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति योग्य बना सकता है।
- (ii) यदि परीक्षार्थी द्वारा दिया गया उत्तर मूल्यांकन निर्देश से भिन्न हो, परन्तु उसका अर्थ या भाव वही निकलता हो तो भी पूरे अंक दिए जाएँ।
- (iii) शब्दों की सीमा कम व अधिक होने पर 10 प्रतिशत तक की रियायत दी जानी चाहिए।
- (iv) एक प्रश्न के जितने भाग हों उनका भागों के अनुसार मूल्यांकन किया जाए, परन्तु प्रश्न के अंक सम्पूर्ण रूप से दिए जाने चाहिए।
- (v) परीक्षार्थी की गलतियों को रेखांकित या परिवेष्टित किया जाए।
- (vi) मूल्यांकन करते समय केवल बिन्दुओं (Points) को वरीयता न दी जाए बल्कि प्रश्न के उत्तर की अभिव्यक्ति एवं विषय-वस्तु को महत्त्व दिया जाए।
- (vii) मूल्यांकन कार्य में 0 से 100 तक scals का प्रयोग किया जाए। पूर्ण अंक देने में हिचक नहीं होनी चाहिए।

SET - A

[इतिहास]

[HISTORY]

- ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता।
- 2. फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्त्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था। 1
- 3. यह इंग्लैण्ड की सरकार द्वारा पास किया गया एक कानून था जिसके अन्तर्गत इंग्लैण्ड में मक्के के आयात पर रोक लगा दी गई थी।
- 4. मालाबार के उप-न्यायाधीश ओ० चन्दू मेनन ने। 1
- 5. 19वीं सदी में रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए पिरवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अकसर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का पिरणाम भी होती है उदाहरण के लिए, औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और पिरवहन साधनों में भी भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर-दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके।

6. 19वीं सदी में बाद के सालों के दौरान बम्बई एक बन्दरगाह के रूप में विकिसत होने लगा जहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादात में रवाना किए जा सकते थे। धीरे-धीरे यह पश्चिमी भारत का एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय केन्द्र भी बन गया। सदी के आखिर तक आते-आते बम्बई देश का एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र बन चुका था।

1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसीडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेजी से फैलने लगा। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह-तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई में आकर बसने लगे। मिल खुलने के बाद और भी ज्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ रुख करने लगे।

- 7. फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रान्तिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए।
 - (i) उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों के एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अन्तर्गत समान अधिकार प्राप्त थे।
 - (ii) पहले के राष्ट्रध्वज के स्थान पर एक नया झण्डा तिरंगा चुना गया।

- (iii) एस्टेट जनरल का चुनाव सिक्रय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा।
- (iv) एक केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भू-भाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए।
- (v) क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली प्रचलित थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई।

अथवा

महात्मा गाँधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जनांदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धित को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शिक्त पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आप को किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रितिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जिरए

सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गाँधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है।

भारत में आने के बाद गाँधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आन्दोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चम्पारन इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

- **8.** (i) सूरत
 - (ii) अमृतसर
 - (iii) बम्बई
 - (iv) डांडी

1 + 1 + 1 + 1 = 4

[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]

[For Blind Candidates Only]

- (i) सूरत
- (ii) अमृतसर
- (iii) बम्बई
- (iv) sish 1 + 1 + 1 + 1 = 4

[राजनीति विज्ञान]

[POLITICAL SCIENCE]

- 9. इस देश की जातीय बनावट बहुत जटिल है देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते है और फ्रेंच बोलते हैं शेष एक फीसदी लोग जर्मन बोलते हैं।
- 10. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियों को संघीय सरकार एवं उनकी इकाईयों (राज्यों) के बीच विभाजित कर दोहरे शासन प्रणाली को अपनाया जाता है।
- 11. अमरीकी धावक, ये एफ्रो-अमरीकी हैं।
- 12. 2006 में देश में 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे।
- 13. ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी-अपनी संस्कृति को अलग मानता है यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो।
- 14. संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक

प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग-साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ।

- 15. राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में प्रायः विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वन्द्विता पाई जाती है यदि राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है और ऐसे में देश विखण्डन की ओर जा सकता है जैसे:
 - (i) उत्तरी आयरलैंड में प्रजातीय एवं राजनीतिक संघर्ष के कारण हिंसा को झेला तथा।
 - (ii) यूगोस्लाविया जो कि धार्मिक तथा जातीय प्रतियोगिता के कारण 6 गणतन्त्रों तथा 2 राज्यों में बँट गया।2
- 16. (i) दबाव-समूह और आन्दोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं।
 - (ii) ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी काम-काज में बाधा पहुँचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं।
 - (iii) व्यवसाय-समूह अक्सर पेशेवर 'लाविस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महँगें विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं।

P. T. O.

- (iv) कुछ मामलों में दबाव-समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं।
- (v) कभी-कभी आन्दोलन राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं।
- (vi) अधिकांशतया दबाव-समूह और आन्दोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। 3
- 17. (i) पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आन्तरिक लोकतन्त्र का न होना।
 - (ii) दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है यह है वंशवाद की चुनौती।
 - (iii) तीसरी चुनौती दलों में (खासकर चुनाव के समय) पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती मुसपैठ की है।
 - (iv) चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है।
- 18. (i) दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है।
 - (ii) अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धान्तों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है।

- (iii) तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है हर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती ही है।
- 19. (i) साम्प्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएँ और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएँ शामिल हैं।
 - (ii) साम्प्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है।
 - (iii) साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबन्दी साम्प्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरूओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है।
 - (iv) कई बार साम्प्रदायिकता सबसे गन्दा रूप लेकर सम्प्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई है।

अथवा

अगर लोकतान्त्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उसमें विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है ?

अगर हम 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतान्त्रिक शासनों और तानाशाहियों के काम-काज की तुलना करें तो पाएगें कि आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकार्ड थोड़ा बेहतर है।

उच्चतर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने में लोकतान्त्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। पर अकेले इसी कारण से लोकतन्त्र को खारिज नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र में पढ़ा है – आर्थिक विकास कई कारकों ; मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतान्त्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अन्तर नगण्य सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतान्त्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अन्तर भले ज्यादा हो लेकिन इसके बावजूद लोकतान्त्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं।

[भूगोल]

[GEOGRAPHY]

20.	33%	1
21.	नवीकरण	1
22.	रोपण कृषि	1
23.	सीमेन्ट	1
1957/1907/(Set : A, B, C & D)		

		(14)	1957/1907			
24.	वनस्प	ति, पशु, जीव-जन्तु, मनुष्य, खनिज, मिट्टी,	धातु। 2			
25.	बनाना	। आसान, पर्वतीय क्षेत्रों, छोटे-छोटे गाँवों, न	ागरों को जोड़ना। 2			
26.		र वस्तुओं का आदान-प्रदान। स्थानीय स्तर गों के बीच वस्तुओं ⁄सेवाओं का आदान-प्रद				
27.		गेक प्रगति के कारण कच्चे माल (कृषि संसाधन वन इत्यादि) बढ़ती जनसंख्या व				
28.	(i)	महानदी	1			
	(ii)	कर्नाटक	1			
	(iii)	केरल	1			
		[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]			
[For Blind Candidates Only]						
	(i)	उड़ीसा	1			
	(ii)	कर्नाटक	1			
	(iii)	केरल	1			
[अर्थशास्त्र]						

[Economics]

29. The national income is the market value of the final goods and services product during the year inclusive of net factor income from abroad.

- 30. The service sector is that sector in which entrepreneurs provide services such as of banking, insurance, trade, health, communication etc. This is also known as tertiary sector.
- **31.** The barter system is one where goods are exchanged with goods without the use of money.1
- **32.** It means integration of our economy with the world economy through foreign trade and foreign investments. In this process, the multinational corporations play a major role by establishing their units in different countries of the world. 1
- **33.** When more people are compelled to do a job which only few can do it then such a situation is termed as disguised unemployment. Disguished unemployment is more common in agriculture. 2

34. Factors Leading to Consumer Exploitation:

The consumer is exploited by the seller or producer due to various factors, some of which are given below.

- (1) Consumers lack the knowledge to judge different kinds of things different kinds of things A consumer has to buy a great variety of things. In one or two fields, he can be an expert and can save himself from cheating. But what about of other fields where he is quite ignorant. There is every possibility of exploitation in such fields.
- (2) New products are coming in the market at a rapid speed New brand of things are coming in the market with such a rapid speed that it becomes quite difficult for the consumer to judge their genuineness. Every time when he goes to the market after some gap, he is simply surprised to see the new varieties of things.
- (3) Consumers are quite ignorant of their rights and duties Most of the consumers do not know as to what are their rights and duties. If they want to lodge their complaints, they do not know where to lodge?

(4) Ill Effects of Advertisement - Most of the consumers are so much attracted by the advertisement of different articles that they do not try to verify the quality of different goods. They bity with a great speed and often repent after wards.

3

35. Objectives of Consumer Protection Act, 1986:

- (a) The right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property.
- (b) The right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services, as the case may be as to protect the consumer against unfair trade practices.
- (c) The right to be assured, wherever possible, access to a variety of goods and services at competitive prices.
- (d) The right to seek redressal against unfair trade practices or unscrupulous exploitation of consumer.

- (e) The right to consumer education.
- (f) The right to be heard and to be assured that consumer's interests will receive due consideration at appropriate price.

OR

Good effects of Globalization on India:

- **Employment:** Globalization has led to the (i) of numerous generation employment Companies opportunities. are moving towards the developing countries to cquire labour force. This obviously caters to employment and income genration to the people in the host country. Also, the migration of people, which has become easier has led to better jobs opportunities.
- (2) **Education**: New numerous educational institutions around the globe, can move out from the home country for better opportunities else where. Thus integrating

with different cultures, meeting and learning from various people through the medium of education is all due to globalization. Developing countries or labour intensive countries have benefited the most.

- (3) **Product quality:** Dut to globalisation, the product quality has been enhanced so as to retain the customers. Today the customers may compromise with the price range but not with the quality of product. Low or poor quality can adversely affect consumer satisfaction.
- (4) **Cheaper prices**: Globalisation has brought in fierce competition in the markets. Since there are varied products to select from, the producer can sustain only when the product is competitively priced. There is every possibility that customer may switch over to another producer if the product is priced heavily.

(5) Free Movement of Capital:

Due to globalization many huge firms are investing in the developing countires by setting up industrial units outside their home country. This leads to foreign direct investment, which helps in promoting economic growth in the host country.

- (6) **Communication**: Due to globalization, circulation of information is no longer a tedious task and can happen in seconds. The internet has significantly affected the global economy, thereby providing direct access to information and products to developing countries.
- (7) International trade: Due to globalization, international trade has broadened its horizon with the help of business process outsourcing. Sometimes in order to concentrate on a particular segment of business it is a practice to outsource certain services. Some countries practice free trade with minimal restrictions on policies.

(8) **GDP Increase:** As the market has widened, the scope and demand for a product has increased. Producers familiarize their products and services according to the requirements of various economics there by tapping the untapped markets. If statistics are of any indication, the GDP of the developing countries has increased twice as much as before.

SET - B

[इतिहास]

[HISTORY]

- एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जिरए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है।
- 2. लुई ऑटो पीटर्स (1819-99) एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की।
- 3. स्टैनली एक पत्रकार और खोजी था।
- 4. चार्ल्स डिकेन्स ने औद्योगीकरण के दौर में शहरी जीवन की दुर्दशा का चित्रण किया है।

- 5. 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और सम्पन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और अजीविका के साधन छीनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों में बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया।
- 6. 1887 में लीवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बुच ने लन्दन के ईस्ट एण्ड में लन्दन के अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लन्दन के कम से कम 10 लाख लोग बहुत ही गरीब हैं और उनकी औसत उम्र 29 साल से ज्यादा नहीं है। बुच ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशाप अस्पताल या पागलखाने में मरने की संभावना ज्यादा है। चार्ल्स बुच ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला की लन्दन को अपने निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4,00,000 कमरे और बनाने होगें।

कुछ समय तक शहर के खाते-पीते बाशिन्दे यही माँग करते रहे कि झोपड़ पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन

धीरे-धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास का इंतजाम करना जरूरी है।

7. आर्थिक क्षेत्र में, उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूँजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मुख्य वर्गों की यह जोरदार माँग थी, 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनिगनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी, 1833 में हैम्बर्ग से न्यरेम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को ग्यारह सीमा-शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 50% सीमा-शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँिक हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना ऐले (Elle) था जिसकी लम्बाई जगह बदलने के साथ घटती-बढ़ती थी।

नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तुओं, लोगों और पूँजी का आवागमन बाधारिहत हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेरोइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर

दिया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी जो उससे पहले तीस से उपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों की राष्ट्रीय एकीकरण को सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया।

अथवा

वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशिसवाद और स्थानीय रीति-रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घालमेल पसन्द नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शिक्तयों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए।

18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आन्दोलन पश्चिमी शिक्तयों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट (विद्वानों का विद्रोह) फ्रांसीसी कब्जे और इसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आन्दोलनों में से था। इस आन्दोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। उन्होंने न्गअन और हातियन प्रान्तों में बगावतों का नेतृत्व किया और एक हजार से ज्यादा ईसाइयों का कल्ल कर डाला।

P. T. O.

वियतनाम के अभिजात्य चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी समन्यवादी परम्पराओं से जन्में थे। जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य-मान्यताओं दोनों का सम्मिश्रण था। वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आभा देखी है। इनमें से कुछ धार्मिक आन्दोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे जबिक कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आन्दोलनों के पक्षधर थे। होआन्हाओ ऐसा ही आन्दोलन था।

8.	(i)	जमशेदपुर	1
	(ii)	कलकत्ता में	1
	(iii)	कलकत्ता, मद्रास, बम्बई (कोई एक)	1
	(iv)	चम्परान	1
		[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]	
		[For Blind Candidates Only]	
	(i)	जमशेदपुर	1
	(ii)	कलकत्ता में	1
	(iii)	कलकत्ता, मद्रास, बम्बई (कोई एक)	1
	(iv)	चम्परान	1

[राजनीति विज्ञान]

[POLITICAL SCIENCE]

9.	सन्	1948 में	श्रीलका	स्वतन्त्र	राष्ट्र	बना।		1

- 10. संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केन्द्रीय प्राधिकार औरउसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है।1
- **11.** (1954 1968) के बीच अमरीका में नागरिक अधिकार आन्दोलन चला।
- 12. 1980 में यह पार्टी बनी, कमल का फूल इसका चिन्ह है।
- 13. (i) संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंन्त्रियों की संख्या समान रहेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार की अनेक शक्तियों को दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपूर्द कर दी गई।
 - (iii) ब्रूसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है।
 - (iv) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है यानि सामुदायिक सरकार। 2
- 14. जब केन्द्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहते हैं।

विकेन्द्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है ?

- 15. सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से उपर और बड़े हो जाते हैं। अमरीका में श्वेत और अश्वेत का अन्तर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब है, बेघर है और भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है जब एक तरह का सामाजिक अन्तर अन्य अन्तरों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है।
- 16. (i) नेपाल में उठे लोकतन्त्र के आन्दोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना, इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया था।
 - (ii) भारत में नर्मदा बचाओ आन्दोलन ऐसे आन्दोलन का अच्छा उदाहरण है।

- (iii) पर्यावरण के आन्दोलन तथा महिला आन्दोलन ठेठ ऐसे ही आन्दोलनों की मिसाल हैं।
- (iv) दबाव-समूहों और आन्दोलनों के कारण लोकतन्त्र की जड़े मजबूत हुई। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी अथवा ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जन-साधारण के हित-समूह तथा आन्दोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगिता निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं।
- 17. (i) अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतन्त्र या निर्दलीय होंगे तो कोई भी चुनौती वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा।
 - (ii) सरकार बन जाएगी पर उपयोगिता संदिग्ध होगी।
 - (iii) देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी होगा।
 - (iv) दलों को इसलिए भी जरूरत है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है।
 - (v) राजनीतिक दल लोकतन्त्र की अनिवार्य शर्त है। 3
- 18. (i) कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे यह सोच लेना भले ही सुखद हो लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना बेहतर है।
 - (ii) कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कई बार परिणाम एकदम उलटे निकलते हैं।

- (iii) लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए।
- (iv) राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ-साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा ?
- 19. (i) यहाँ सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं।
 - (ii) अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र होता है।
 - (iii) विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर क्षेत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।
 - (iv) संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है।
 - (v) अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है।
 - (vi) वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं।

1957/1907/(Set : A, B, C & D)

P. T. O.

(vii) संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं ; देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना।

अथवा

- (i) विधायकों और सांसदों को दल-बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया।
- (ii) चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी सम्पत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथपत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया।
- (iii) चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया।
- (iv) राजनीतिक दलों के आन्तरिक कामकाज को व्यवहारिक करने के लिए कानून बनाया जाए।
- (v) राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में (करीब एक तिहाई) जरूर टिकट दें।
- (vi) चुनाव का खर्च सरकार उठाए।

[भूगोल]

[GEOGRAPHY]

20. अनवीकरण कभी-कभी चक्रीय

1

21. गेहूँ, चना, जौ

1

	(31) 1957/19	07				
22.	थोरियम	1				
23.	श्रीनगर	1				
24.	बाँध से सिंचाई, पेयजल, जल, विद्युत, बाढ़ो को रोकना इत्यादि।	2				
25.	लम्बी दूरी की यात्रा, भारी वस्तुओं का लेना जाना, सड़क परि से सस्ता किराया।	वहन 2				
26.	उद्योगों से निकलने वाला धुआँ, अवशिष्ट पदार्थ पानी में डा इत्यादि।	लना, 2				
27.	भारत का उष्ण कटिबन्ध में स्थित होने से सारा साल सूर्य किरणों द्वारा ताप की निरन्तर प्राप्ति सम्भव हो सकती है।	की 6				
28.	(i) नर्मदा नदी	1				
	(ii) आन्ध्रप्रदेश	1				
	(iii) पंजाब अमृतसर	1				
	[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]					
	[For Blind Candidates Only]					
	(i) गुजरात	1				
	(ii) आन्ध्र प्रदेश	1				
	(iii) पंजाब	1				
[अर्थशास्त्र]						
[Economics]						
29.	Such activities which transform raw materials primary products into useful commodithrough some process of manufacturing called activities of secondary sector.	ties				
1957	1957/1907/(Set : A, B, C & D) P. T. O.					

- 30. Loans provided by banks and co-operatives are called formal sector loans.
- 31. Large companies which operate in many countries of the world are called multinational corporations.
- 32. December 24 is celebrated as NationalConsumer's Rights Day.
- 33. Self Help Groups has mambers between 15 to20. Different members of the group pool their savings and form their co-operatives which advance loans to their needy members.
- **34.** In a barter system, commodities are exchanged with commodities without the use of money. But in such a system, two parties are required who are ready to sell and buy each other's commodities. This is called double corincridence of wants. But if transactions are made in money, then there is no any such need of double coincidence of wants. With the help of money one can buy a commodity of his choice when-

ever he so desires. He need not wait for the other person to agree to exahinge his goods with his own goods. Thus money makes the economic activities quite independent from each other.

- **35.** (1) The different sources of loans are grouped as formal sector loans and informal sector loans. Formal sector loans are such loans which are taken either from the banks or the cooperative societies. While informal sector loans are those which are taken from money lenders, traders, employers, relatives and friends.
 - (2) In case of informal sector of loans, the rate of interest is quite high i.e. 3 to 5% per month which comes to (12 × 3 = 36%) or (5 × 12 = 60%) a year which is quite high. On the ohter hand, If the loan is taken from a bank, the rate of interest is usually very low about 8 to 10% a year. Therefore one would try to take a loan from formal sector rather than from a informal sector.

(3) In formal sector of loans, there is no exploitation as is the case with the informal sector of loans. In the informal sector, the trader would desire to buy the produce of the formers at a low price but a bank would never resort to such an exploitation.

As the people are more benefited by the formal sources of credit, so effort should be made to expand formal sources of credit. 6

OR

It is quite necessary to have a public sector because of the following reseans:

(1) The public sector provides many essential things such as supply of electricity to domestic sector and Industrial sector at reasonable rate which private sector can not provide.

- (2) The public sector can spend money on such facilities which require heavy investment such as roads, dams, railways, bridges etc. in which private sector does not take interest due to long gestation period.
- (3) The motive of public sector is the welfare of the people and not to earn profit whereas private sector motive is to earn profit and not welfare of the people.
- (4) To provide basic facilities such as quality education, health services, drinking water, housing facilities etc. is the primary responsibility of the government that is why public sector is essential for a country.
- (5) Public sector provides food items such as wheat, sugar, rice etc. to poor at cheap rates than market rate.
- (6) The public sector purchases wheat and rice of the formers at support price otherwise they would have been exploited private traders.

SET - C

[इतिहास]

[HISTORY]

- 1. उदारवाद यानी Liberalism शब्द लातीनी भाषा के मूल Liber पर आधारित है जिसका अर्थ है 'आजाद'।
- 2. एक साझा नस्ली जन जातीय या संस्कृतिक उदगम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है जैसे : अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश।
- 3. ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज (देशी खर्चे) का निपटारा होता था। 1
- 4. चार्ल्स डिकेन्स ने, डिकेन्स ने केवल न लाभ के लोभ की आलोचना की बल्कि उन विचारों को भी आड़े हाथों लिया जो इन्सानों को महज उत्पादन का औजार मानते हैं।
- 5. महामन्दी के कारण :- सन् 1929 से लेकर 1933 तक का काल महामन्दी के काल के रूप में जाना जाता है। इस मन्दी के मुख्य कारण इस प्रकार थे :-
 - (i) कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन
 - (ii) अमेरिकी ऋण का मिलना बन्द होना

- (iii) बैकों का बन्द होना जिसके परिणामस्वरूप कारखाने बन्द होने लगे एवं बेरोजगारी बढ़ने लगी। (नोट : उपर्युक्त तीन या अन्य कोई)
- 6. 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक-चौराहों पर बेची जा रही थी जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए।

19वीं सदी के अन्त से जाति भेद के बारे में तरह-तरह की पुस्तिकाओं और निबन्धों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आन्दोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामिगरी (1871) में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। मद्रास में ई० बी० रामास्वामी नायकर ने जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं जाति प्रथा पर जोरदार कलम चलाई गई उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए कानपुर के मिल मजदूर काशीबाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की।

7. राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों किस्सों और संगीत के राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आन्दोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रुमानी

कलाकारों और कवियों ने तर्क-वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतदृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया।

जर्मन दार्शनिक योहान गाटक्रीड जैसे रूमानी चिन्तकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों (das. volk) में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक-नृत्य में प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापिस लाना नहीं था बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुँचाना था।

भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अथवा

पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नयी स्थिति पैदाकर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध सम्बन्धी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लम्बा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट

की बोरियाँ, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा।

युद्ध के बाद भारतीय बाजार मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हॉसिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमरीका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

8.	(i)	मुम्बई	1				
	(ii)	चौरी-चौरा	1				
	(iii)	लाहौर	1				
	(iv)	कलकत्ता	1				
	[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]						
	[For Blind Candidates Only]						
	(i)	मुम्बई	1				
	(ii)	चौरी-चौरा	1				
	(iii)	लाहौर	1				
	(iv)	कलकत्ता	1				
1957	1957/1907/(Set : A, B, C & D) P. T. C						

1

[राजनीति विज्ञान]

[POLITICAL SCIENCE]

10.	विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बाँटा गया है, ये तीन	सुचियँ
	इस प्रकार हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवृत्ति सूची।	1

9. 1970 - 1993 के बीच चार संशोधन किए गए।

- **11.** सन् 2001 में।
- 12. बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमन्त्री थे।
- 13. (i) शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा।
 - (ii) सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों का सत्ता का बँटवारा हो सकता है।
 - (iii) सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषायी और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है।
 - (iv) सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आन्दोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं।
- 14. प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की पिरषद् है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जिरए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने

वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख-रेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है। 2

15. भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधान :

- (i) भारत के सभी नागरिकों एवं समुदायों को धार्मिक स्वतन्त्रता का संवैधानिक अधिकार देना।
- (ii) भारत में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है बल्कि सर्वधर्म समभाव के सिद्धान्त को अपनाया है।
- (iii) संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। 2

16. दबाव-समूह एवं राजनीतिक दल में अन्तर:

- (i) राजनीतिक दल एक विचारधारा पर आधारित लोगों का समूह होता है जबिक दबाव-समूह एक समान हितों वाले लोगों का समूह होता है।
- (ii) राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है, जबिक दबाव-समूह का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना होता है।
- (iii) राजनीतिक दल साधारणतया जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं जबिक दबाव-समूह अपने समूह के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं।

नोट: उपयुक्त तीन या अन्य कोई अन्तर।

- 17. लोकतन्त्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि :
 - (i) नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है।
 - (ii) इससे फैसलों में बेहतरी आती है।
 - (iii) व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है।
 - (iv) टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और
 - (v) इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। 3
- 18. औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं उनका दमन इस प्रकार होता है:
 - (i) महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है जबिक पुरुषों में 76% है।
 - (ii) अब भी ऊँची तनख्वाह वाले ऊँचे पदों पर पहुँचाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है।
 - (iii) समान काम के समान मजदूरी, पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है।
 - (iv) भारत के अनेक हिस्सों में माँ-बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं।

19. राजनीति में जाति निम्नलिखित रूप ले सकती है:

- (i) जब पार्टियाँ चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए।
- (ii) जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों को उचित जगह दी जाए।
- (iii) राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।
- (iv) सार्वभौम व्यस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबन्द करने के लिए सिक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नयी चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता है।
- (v) राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं।

अथवा

अलग-अलग देशों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतन्त्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियाँ हैं।

- (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतान्त्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है।
- (ii) अधिकांश स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतान्त्रिक शासन के बुनियादी सिद्धान्तों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं को लागू करना शामिल है।
- (iii) तीसरी चुनौती लोकतन्त्र को मजबूत करने की है। हर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है। इसमें लोकतान्त्रिक संस्थाओं और बरताओं को मजबूत बनाना शामिल है। अलग-अलग समाजों में आम आदमी को लोकतन्त्र से अलग-अलग अपेक्षाएँ होती है इसलिए यह चुनौती दुनियाँ के अलग-अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले सकती है।

(45) [भूगोल]

[GEOGRAPHY]

14147.53	'
चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का	1
एल्यूमिनियम	1
पाइप लाइन	1
पुराने औजारों की सहायता से फसलों को बोना, जगह बदल- भूमि कृषि करवाना।	बदल 2
Iron and steel copper industries.	2
जो दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में पदार्थ उप करवाना।	ालब्ध
खिनज बहुत ही सीमित मात्रा में प्रकृति ने दिए हैं और अ और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जरूरत पड़ेगी और बनने में बहुत बड़ा समय लगता है।	
लाभ : सिंचाई विद्युत उत्पादन घरेलू और औद्योगिक उद्यमों, आपूर्ति, बाढ़ नियन्त्रण, मनोरंजन, आन्तरिक नौचालन, म पालन।	
हानियाँ : जल प्रवाह अवरुद्ध होना, तलछट का कम अ अत्यधिक सिंचाई व मृदाओं का लवणीकरण, अमीर और अ जमीदारों सामाजिक दूरी।	
7/1907/(Set : A, B, C & D)	. O
	चावल, ज्चार, बाजरा, मक्का एल्यूमिनियम पाइप लाइन पुराने औजारों की सहायता से फसलों को बोना, जगह बदल- भूमि कृषि करवाना। Iron and steel copper industries. जो दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में पदार्थ उप करवाना। खनिज बहुत ही सीमित मात्रा में प्रकृति ने दिए हैं और अ और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जरूरत पड़ेगी और बनने में बहुत बड़ा समय लगता है। लाभ : सिंचाई विद्युत उत्पादन घरेलू और औद्योगिक उद्यमों, आपूर्ति, बाढ़ नियन्त्रण, मनोरंजन, आन्तरिक नौचालन, म् पालन। हानियाँ : जल प्रवाह अवरुद्ध होना, तलछट का कम अत्यिधक सिंचाई व मृदाओं का लवणीकरण, अमीर और जमीदारों सामाजिक दूरी।

			(46)	1957/1907	
28.	(क)	नारोरा बांध गंगा न	दी	1	
	(ख)	छत्तीसगढ़		1	
	(ग)	गोआ		1	
		[केवल दृष्टिही	न परीक्षार्थियों के लिए	[]	
		[For Blind	Candidates On	ly]	
	(i)	गंगा नदी		1	
	(ii)	छत्तीसगढ़		1	
	(iii)	गोवा		1	
		[,	अर्थशास्त्र]		
		[EC	ONOMICS]		
29.	The	middle east		1	
30.). When we produce goods by exploiting natural				
	sources such activities are called activities of the				
	prin	nary sector.		1	
31.	Collateral is a sort of security in the shape of				
	land, building, vehicle, livestock, deposits with				
	banks which the borrowers give to the lender				
	unt	il the loan is pa	id.	1	
1957	/1907	″/(Set : A, B, C & □))		

- **32.** Because they are cheaper and have new design.1
- articles like garments, footwear, sports items with small producers and get the things prepared at cheap rates according to their standard and then sell these articles under their brand names to the customers in different countires. They keep margin of profits with them and thus make huge profits. They place these order due to cheap labour in developing countires.
- **34.** The most imporatant feature of the Consumer Protection Act, 1986 is that it set up consumer courts at the district, state and national level.
 - (i) At the district level, it is called the district forum.
 - (ii) At the state level, It is called the state consumer disputes redressal commission.

(iii) At the national level, It is called the national consumer disputes redressal commission.

35. Tertiary sector importance in India:

- (i) It is the duty of the government to speed up the process of development in the economy.
 - To accelerate the development process tertiary sector provides basic services to the people like hospitals, educational institutions, post offices, police stations, communication services etc.
- (ii) The development of agriculture and industry has also led to the development of services like transport and trade.
- (iii) With the rise in the income level of people, the standard of living of people has also rise, therefore demand for services like hotels, shipping, tourism, private school and private hospital are increasing day by day.

- (iv) New services such as information communication technology has become quite essential.
- (v) Many different kinds of people like shopkeepers repair persons, transport persons engaged in different services are also growing rapidly.6

OR

The banks play on comportant role in the economy of a country.

- (i) They keep the money of the people in safe custody otherwise people can become an easy prey of thieves or robber.
- (ii) They give interest on the money deposited by the people. Thus they add to the income of the farmily. Many familier survive on the bank interest.
- (iii) The banks deposited the surplus money of the people and lends it to needy person.

- (iv) Banks provide cheap loans to a large number of people for constructing their houses.
- (v) Banks promote agriculture by providing loans to the formers who can increase their production by bringing new form implements and make better arrangements for the irrigation of their fields.
- (vi) Banks boost the country's industry also by providing cheap loans to the industrialists.
- (vii) The banks are the back bone of the country's trade also.
- (viii) Banks employee a large number of people and as such they solve the employment problem also.

SET - D

[इतिहास]

[HISTORY]

1. शुल्क संघ, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। 1

1

- 2. जर्मेनिया : जर्मेनिया जर्मनी के चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झण्ड़े पर बनाया चूँकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और जहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। 1
- वीटो : निषेधाधिकार, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है।
- 4. बंकिंम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने
- 5. (i) देश का आयात-निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया।
 - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूँ की कीमत 50% गिर गई।
 - (iii) कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई।
 - (iv) पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए।
 - (v) भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा।
 - (vi) औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। 3
- 6. 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देशी प्रेस का मुँह बन्द करने की माँग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार-पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते

1957/1907/(Set : A, B, C & D)

P. T. O.

गए त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियन्त्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी आइरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी। अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी।

7. 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोविनिया, सर्बिया और मन्टिनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लेव (दास) पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था बाल्कन क्षेत्र में रुमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आन्तरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था किन्तु इसमें इसे बहुत सफलता नहीं मिली। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएँ उसके चंगुल से निकलकर स्वतन्त्रता की घोषणा करने लगे।

जैसे-जैसे विभिन्न स्लेव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतन्त्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंिक बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शिक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शिक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएँ खुलकर सामने आई। जर्मनी, इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रो-हंगरी कर ताकत बाल्कन पर अन्य शिक्तयों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अन्ततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 6

अथवा

औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में हिन्दुस्तानियों को आमतौर पर कमजोर, आपस में विभाजित और अंग्रेजों पर निर्भर बताया जाता था। इस इतिहास से भारत के नए प्रशासकों और बौद्धिकों को असन्तोष होना लाजिमी था। न ही उनका विश्वास सुरों-असुरों के हैरतअंगेज और अंधविश्वासी कारनामों व किरदारों से पटी पारम्परिक पौराणिक कहानियाँ पर जम सकता था। ऐसे मानस को भूत के एक नए दृष्टिकोण की दरकार थी, वे यह

जताना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र चेतना वाले और इतिहास में भी आजाद-ख्याल रहे थे।

बंगाल में कई सारे उपन्यास मराठों व राजपूतों को लेकर लिखे गए। इनसे अखिल भारतीयता का अहसास पैदा हुआ। उनमें कितपय राष्ट्र रूमानी साहस, वीरता और त्याग से ओत-प्रोत था। ये ऐसे गुण थे जिन्हें 19वीं सदी के दफ्तरों और सड़कों पर पाना मुश्किल था इस तरह उपन्यास में गुलाम जनता ने अपनी चाहत को साकार करने का जरिया ढूढां। भदेव मुखोपध्याय (1827-94) कृत अंगुरिया बिनिमाय (1857) बंगाल में लिखा जाने वाला पहला ऐतिहासिक उपन्यास था इसके नायक शिवाजी धूर्त और कुटिल औरंगजेब से कई बार लोहा लेते हैं। मानसिंह शिवाजी को शान्ति-समझौता के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन यह समझने के बाद कि औरंगजेब उन्हें नजरबन्द करना चाहता है शिवाजी भाग निकलते हैं और फिर से जंग के मैदान में नजर आते हैं। उनके साहस और जीवन का प्रेरणा स्रोत यह विश्वास है कि वे हिन्दुओं की आजादी के लिए लड़ रहे राष्ट्रवादी हैं।

उपन्यास में किल्पित राष्ट्र में इतनी ताकत थी कि इससे प्रेरित होकर असली राजनीतिक आन्दोलन उठ खड़े हुए। बंकिंम का आनंदमठ (1882) मुसलमानों से लड़कर हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिन्दू सैन्य-संगठन की कहानी कहता है इस एक उपन्यास ने तरह-तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।

		(55)	1957/1907		
8.	(i)	1860 के दशक में एल्गिन मिल कानपुर	में खुली। 1		
	(ii)	अहमदाबाद।	1		
	(iii)	बम्बई।	1		
	(iv)	भरूच या भृगुकच्छ या सूरत।	1		
		[केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए]		
		[For Blind Candidates Only	у]		
	(i)	1860 के दशक में एल्गिन मिल कानपुर	में खुली। 1		
	(ii)	अहमदाबाद।	1		
	(iii)	बम्बई।	1		
	(iv)	भरूच या भृगुकच्छ या सूरत।	1		
		[राजनीति विज्ञान]			
		[POLITICAL SCIENCE]			
9.	क्रिश्चि	ायन डेमोक्रेटिक पार्टी या सोशल डेमोक्रेटिक	पार्टी। 1		
10.	10. 1 नवम्बर, 1956 को।				
11.		ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक सांस्वृ नताएँ ज्यादा गहरी नहीं होती।	वृतिक या जातीय 1		
12.		देश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2 का 29वां राज्य बना।	014 को तेलंगाना 1		
1957	7/1907	/(Set : A, B, C & D)	P. T. O.		

13. भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से समान विशेषता : भारत एवं बेल्जियम दोनों देशों की संघीय व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर सरकार के कार्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

भिन्न विशेषता : बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार हैं। किसी भी राज्य के पास विशेषाधिकार नहीं है जबिक भारत में जम्मू-काश्मीर राज्य को अलग विशेषाधिकार दिए है जिसमें उसका अपना संविधान है।

- 14. (i) अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
 - (ii) निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटे आरक्षित हैं।
 - (iii) कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
 - (iv) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतन्त्र संस्था का गठन किया गया है।
 - (v) राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। 2

15. भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जेसे लोकसभा में महिला सासंदों की संख्या अभी कुल सदस्यों की दस फीसदी तक भी नहीं पहुँची है। राज्यों की विधान-सभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5 फीसदी से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीकी और लेटिन अमरीका के कई विकासशील देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ पहुँची हैं पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है।

16. राजनीतिक दलों के बेहतर कामकाज हेतु सुझाव :

- (i) राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र हेतु नियमित संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए।
- (ii) दलीय अनुशासन होना चाहिए।
- (iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों हेतु खर्च में सहायता करनी चाहिए।
- (iv) दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन।
- (v) आन्तरिक काम को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए।
- 17. लोकतान्त्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि यह सदभावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाए अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट या हिंसक लेने का आदेश कम हो जाता है।

- **18.** (i) शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा
 - (ii) सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बँटवारा हो सकता है।
 - (iii) सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषायी और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है।
 - (iv) सत्ता के बँटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आन्दोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। 3
- 19. (i) दल चुनाव लड़ते हैं।
 - (ii) दल अलग-अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं।
 - (iii) पार्टियाँ देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है।
 - (iv) नीतियों और बड़े फैसलों के मामलों में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं।
 - (v) चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबन्द करते हैं।
 - (vi) जनमत निर्माण के दल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - (vii) दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँचाते हैं। 6

अथवा

अभी तक इसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है ? पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एकतरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त होती है बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज अनेक रूप लेती है:

- (i) हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है।
- (ii) राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबन्दी भी हुई है, जैसे 'झगड़ा' और 'पिछड़ा'।

इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएँ निभाती हैं और एक तरह से यही चीजें दुनियाँ भर की राजनीति में चलती हैं।

[भूगोल]

[GEOGRAPHY]

20.	नवीकरण	1			
21.	तरबूज, खरबूजा, सब्जियाँ, खीरा इत्यादि।	1			
22.	इलेक्ट्रॉनिक्स	1			
23.	स्थल (सड़क परिवहन)	1			
24.	बचे खुचे वनस्पति गोबर और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से वाली गैस।	पैदा होने 1			
1957	1957/1907/(Set : A, B, C & D) P. T. O.				

			(60)	1957/1907
कच्चा	माल की	पूर्ति		1
ক্তর্जা				
परिवह	इन के साध	न		
सस्ती	भूमि की	उपलब्धता		
जलपूर्	र्ते			2
एक ह और	ही फसल ज अधिक श्रम	ो झाड़ी वे ओर पूँर्ज	हे रूप में या ो खर्च करके	वृक्ष के रूप में लगाई जाए की जाए।
क्योंवि	कृषि पदा	र्थ जो कच	वे माल के स	न्प में
खनिज	ा पदार्थ	" "	" "	Transport to
वनीय		,, ,, ;	" "	
	उ	द्योग		
तैयार	माल के स	न्प में		3
	ब	जार		
(i)	सतलुज			1
(ii)	पश्चिमी ब	ांगाल		1
(iii)	महाराष्ट्र			1
	[केव	ल दृष्टिहीन	न परीक्षार्थियों	के लिए]
	[For	Blind (Candidate	es Only]
(i)	सतलुज			1
(ii)	पश्चिम बं	गाल		1
(iii)	महाराष्ट्र			1
	ऊर्जा परिवह सस्ती जलपूर्ण एक है और क्योंकि खनिज् वनीय (i) (ii) (iii) (iii)	ऊर्जा परिवहन के साध सस्ती भूमि की उ जलपूर्ति एक ही फसल ज और अधिक श्रम क्योंकि कृषि पदा खनिज पदार्थ वनीय तैयार माल के स बा (i) सतलुज (ii) पश्चिमी ब (iii) महाराष्ट्र [केवः [For (i) सतलुज	परिवहन के साधन सस्ती भूमि की उपलब्धता जलपूर्ति एक ही फसल जो झाड़ी वें और अधिक श्रम और पूँजी क्योंकि कृषि पदार्थ जो कव् खनिज पदार्थ "" वनीय """ वशींक कृषि पदार्थ जो कव् खिनज पदार्थ "" वशोंग तैयार माल के रूप में बाजार (i) सतलुज (ii) पश्चिमी बंगाल (iii) महाराष्ट्र [केवल दृष्टिहीन [For Blind () (i) सतलुज (ii) पश्चिम बंगाल	कच्चा माल की पूर्ति ऊर्जा परिवहन के साधन सस्ती भूमि की उपलब्धता जलपूर्ति एक ही फसल जो झाड़ी के रूप में या और अधिक श्रम और पूँजी खर्च करके क्योंकि कृषि पदार्थ जो कच्चे माल के रू खनिज पदार्थ """" वनीय """" तैयार माल के रूप में बाजार (i) सतलुज (ii) पश्चिमी बंगाल (iii) महाराष्ट्र [केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों [For Blind Candidate (i) सतलुज (ii) पश्चिम बंगाल

[अर्थशास्त्र]

[ECONOMICS]

- **29.** It means the development of an individual in such a way that he could lead to a happy life according to his cherished wish and goals.
- **30.** Unorganised sector is one which is outside the purview of the government and where no rules and regulation are follwed.
- **31.** Because these deposits can be withdrawn any time on demand by the depositors.
- **32.** It means international organisation for standardisation which has its headquarter at Geneva. It does the standardization work at the international level.
- **33.** Industries can better be classified on the basis of their ownership under the following categories.
 - (i) **Public Sector Industries**: Industries owned by the state or its agencies are called public sector industries for example, The Indian Railways, The iron and steel industry at Bhilai and Durgapur, oil natural gas commission are some example of public sector industries.

- (ii) **Private Sector Industries**: Industries owned by Individuals or firms formed by individuals are called private sector industries. For example Tata Steel Company and Reliance Industries Limited are some example of Private Industries. 2
- **34.** There is a great demand of loans or credit because of the following reasons :
 - (i) It plays a great role in the development of a country by creating better facilities for agricultural and industrial activities.
 - (ii) People demand loans to set up their business.
 - (iii) People demand loans to construct their houses.
 - (iv) People demand loans to pursue higher education.
 - (v) People demand loans to purchase consumer durable goods such as television, car etc.
- **35.** There are many who are against globalisation. They put forward many arguments in support of their view.

- (i) According to critics of globalisation large corporations invest in poor countries only because they can make greater profits from low level wages or because they can get access to their natural resources.
- (ii) The free market forces does nothing to redress the redistribution of wealth and therefore inequality in the world has reason more than before.
- (iii) Global companies generally locate polluting industries in poor countries therefore degrade their environment.
- (iv) Due to globalisation, captalism has spread throughout the world in which the labour of the poor countires is exploited for the benefit of the rich.
- (v) Glabalisation has led to a lowering of wages and work conditions of labour have detercorated more than before because globalisation generally does not allow unions to defend their workers right.
- (vi) Globalisation has destroyed the forestwealth of developing countries.6

OR

Factors Leading to Consumer Exploitation:

- (i) A consumer has to buy a great variety of things. In one or two fields, he can be an expert and save himself from being cheated. But what of other fields where he is quite ignorant. There is every likelihood of his being exploited in such fields.
- (ii) New brand of things are coming in the market with such a rapid speed that it becomes quite difficult for the consumer to select good quality of things. In this process, he is cheated many times.
- (iii) Most of the consumers do not know what are their rights and duties. In case if they want to lodge a complaint against a any trader, they do not know where to file a complaint. They lock consumer education.
- (iv) Most of the customers are so much attracted by the advertisement of different articles that they do not try to verify the quality of different goods. They buy immediately and often repent afterwords.